अध्यक्ष महोदय

सत्यमेव जयते

असंशोधित

3 1 MAR 2006

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रॅ०सं०...788....तिथि...8/5...

बि० स० मु० (एल० ए०) 219—गोनो—1,000—9-6-2004

टर्न-४/मधुप/३१.३.२००६

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- 'घ'- ३२ का पूरक ..क्रमशः...

श्री जीतन राम माँझी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बैकलॉग और आरक्षण के संबंध में बात कही । महोदय, नियम और परिनियम के साथ-साथ परम्पराएँ भी होती हैं । हमलोग जानते हैं कि विश्विविद्यालय यू०जी०सी० के कंट्रोल और निर्देशन में चला करता है तो सबसे पहले, प्रबंध समिति वहाँ प्रमुख समिति होती है और उसको सभी प्रकार के अधिकार और शक्ति प्राप्त हैं तो हम जानना चाहेंगे कि क्या राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध समिति ने ऐसी अनुशंसा की थी कि जो अहर्त्ता होती है नेट की या दो वर्ष का जो समय है, उसको शिथिल करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया जारी की जाए ? यह सत्य है या नहीं ?

दूसरी बात, इसी प्रकार के समकक्ष विश्वविद्यालय की मुझको जानकारी है - जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय की वहाँ की प्रबंध समिति के द्वारा निर्णय लिया गया और एक-दो वर्ष की जो अहर्त्ता है और नेट का जो क्वालिफिकेशन है, जहाँ तक अनुसूचित जाति का मामला है, उसको वहाँ शिथिल किया है और नियुक्ति की तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या बिहार सरकार जो सामाजिक न्याय की सरकार है, दलितों के मसीहा की सरकार है, हम जानना चाहेंगे कि क्या इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ भी नियम को शिथिल करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया जारी करेंगे या नहीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह, मंत्री : महोदय, मैंने बार-बार कहा, फिर मैं उस बात को दुहराता हूँ । माननीय सदस्य, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की प्रबंध समिति है, उसके बोर्ड ने निर्णय किया ६ अक्टूबर, २००४ को, उसने रिलैक्सेशन किया नेट पर उसके साथ शब्द जोड़ा.....

श्री भोला सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता और जवाब देने वाले - दोनों एक ही राशि के लोग हैं । प्रश्न कुछ है और जवाब कुछ आ रहा है । हमारा आग्रह है अध्यक्ष महोदय, कि आप प्रश्नकर्त्ता सदस्य, माननीय मंत्री के साथ इन तमाम विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए अपने चेम्बर में एक बैठक बुला लें और राजेन्द्र कृषि विश्विद्यालय के संबंध में एक सांगोपांग विचार-विमर्श हो जाये ।

श्री श्याम रजक : ठीक रहेगा ।

श्री नरेन्द्र सिंह : महोदय, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है । इसमें जो प्रश्नकर्त्ता हैं, और भी जो माननीय सदस्य हैं, जिन लोगों ने पूरक प्रश्न इसपर पूछा है, विभाग के लोग भी रहेंगे, आप इसको देख लें ।

अध्यक्ष : आसन इसको देख लेगा ।

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- 'च'- ४१

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय,

खण्ड-१ : उत्तर अस्वीकारात्मक है । राष्ट्रीय सम विकास योजना राज्य में वित्तीय वर्ष २००२-०३ के दौरान लाया गया । इसके तहत दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (२००२-०७) में ४००० करोड़ रूपये की शत-प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान राशि

राज्य को प्राप्त होना था । वर्ष २००२-०३ से मार्च २००६ तक केन्द्र से १४७२.३२ करोड़ रूपया स्वीकृत हुआ है । इस योजना के अन्तर्गत कार्य, भारत सरकार के कार्यकारी एजेन्सी के माध्यम से, जैसे- पावर ग्रीड कॉरपोरेशन, सी०पी०डब्लू०डी०, नाबार्ड इत्यादि द्वारा कराया जाता है एवं भारत सरकार द्वारा राशि सीधे इन एजेन्सियों को विमुक्त किया जाता है । वार्षिक योजना २००६-०७ को अन्तिम रूप देने के दौरान योजना आयोग में हुई विमर्श बैठक के दौरान यह संकेत मिला कि राष्ट्रीय सम विकास योजना की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाकर २००७-०८ तक की जा सकती है । इसके आलोक में यह उम्मीद की जाती है कि इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली ४००० करोड़ रूपये की राशि का व्यय संभव हो सकेगा ।

खंड-२ : प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री महेश्वर सिंह : महोदय, जो भी राशि १४०० करोड़ के लगभग मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है, महोदय, मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि उसमें चाहे जो भी एजेन्सियाँ हों, जो इन्होंने बताया है, एक भी पैसा राज्य में खर्च नहीं हुआ है और इन्होंने कहा कि इसका समय बढ़ा दिया जायेगा ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि रूपया पड़ा हुआ है और राज्य में विकास के कार्य, जैसे- स्कूल, हाई-स्कूल, सुनिश्चित रोजगार योजना, आदि जितनी भी योजनाएँ थी, मैं पूछना चाहता हूँ इस १४००-१५०० करोड़ की राशि से जो विकास कार्य होते, अभी तक एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है ।

...क्रमशः...

टर्न-५/अंजनी/दि० ३१.०३.०६

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-च-४१ का पूरक

...क्रमशः...

श्री महेश्वर सिंह : ३१ मार्च अभी लैप्स भी नहीं हुआ और समय बढ़ा दिया गया तो फिर क्या आगे भी एक वर्ष का उसमें समय लेकर रूपया खर्च करेंगे ? क्योंकि और भी रूपया इनको मिलेगा और जबतक रूपया खर्च नहीं होगा तबतक केन्द्र से भी दूसरा रूपया भी नहीं मिलेगा । इसके लिए कोई भी व्यक्ति, आपका इंजीनियरिंग सेल या प्रशासन कोई भी दोषी हो, मैं पूर्वी चम्पारण का उदाहरण दे रहा हूँ, वहाँ पर १५ करोड़ रूपया गया लेकिन एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ । क्या सरकार इन रूपयों को, जो सम विकास योजना के तहत मिला हुआ है, उस राशि से अगर आप बिहार का विकास करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कौन-सा उपाय करना चाहते हैं ? अगर कोई दोषी नहीं है तो आखिर कारण क्या है कि रूपया खर्च नहीं हो रहा है, सरकार यह स्पष्ट करे ?

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसके संबंध में कहना चाहता हूँ कि योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजना अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा प्राधिकृत समिति की बैठक के द्वारा की जाती है और प्राधिकृत समिति की बैठक में बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आयुक्त एवं सचिव, योजना विकास विभाग, बिहार तथा आवश्यकतानुसार मुख्य सचिव भी भाग लेते हैं । इस बैठक में योजना के कार्यान्वयन में आनेवाली बाधायें, समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य सरकार के प्रतिनिधि नियमित रूप से अपनी पक्ष प्रस्तुत करते हैं । मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा जिन-जिन केन्द्रीय एजेंसियों को राशि आवंटित की गयी है, उन एजेंसियों ने राशि खर्च क्यों नहीं की, योजना क्यों नहीं पूरी हुई, इस बारे में आज ही महोदय योजना आयोग को लिखूँगा कि समीक्षा कराकर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ।

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ...

अध्यक्ष : घड़ी देख लीजिए रामदेव वर्मा जी ।

श्री रामदेव वर्मा : महोदय, मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : यह अंतिम प्रश्न होगा ।

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूँ कि १५०० करोड़ राशि जो है वह तो ठीक है राष्ट्रीय एजेंसियाँ हैं, केन्द्र सरकार की एजेंसियाँ हैं, ४०० करोड़ को इन्होंने प्रश्न में कबूल किया है कि यह खर्च नहीं होने के लिए योजना आयोग से और इन्होंने एक्सटेंसन मांगा है और एक्सटेंसन दे भी दिया गया । सवाल एक ही है कि ४०० करोड़ राशि नहीं खर्च होने के पीछे आपकी जो एजेंसी हैं, जो सरकारी इंजीनियरिंग सेल है, वह सक्षम नहीं है । आप समय बढ़ाते रहिए-एक साल-दो साल लेकिन समय के अंतर्गत ४०० करोड़ रूपया खर्च करने के लिए उसको सक्षम कीजियेगा कि नहीं ? इंजीनियर कितने हैं ? चीफ इंजीनियर नहीं है, एसिसटेंट इंजीनियर नहीं है,

कनीय अभियन्ता नहीं है, जिसके चलते ४०० करोड़ रूपया खर्च नहीं कर पा रहे हैं । टाईम बढ़ाते रहिए, उससे कुछ होनेवाला नहीं है ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो चार हजार करोड़ रूपया टेंथ फाइव ईयर प्लान में मिलना था, मिला केवल लगभग १५०० करोड़ और अगर इस योजना को, राष्ट्रीय सम विकास योजना को ११वीं पंचवर्षीय योजना में अगर बढ़ाया नहीं जायेगा तो बिहार को ढ़ाई हजार करोड़ रूपया का नुकशान हो जायेगा । इसमें माननीय मुख्यमंत्रीजी प्रधानमंत्री से मिलने गये थे, योजना आयोग से हमलोगों ने आग्रह किया था कि राष्ट्रीय सम विकास योजना को ११वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कराया जाय ताकि हमको चार हजार करोड़ रूपया मिल सके । इसलिए अध्यक्ष महोदय जो १५०० करोड़ रूपया है, बाकी जो नहीं मिल पाया है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर भेजने में काफी विलम्ब हुआ, जिसके कारण पैसा नहीं मिल पाया । लेकिन जो १५०० करोड़ रूपया मिला, वह लैप्स नहीं करेगा, वह सरेंडर नहीं होनेवाला है । अध्यक्ष महोदय, चिन्ता यह है कि बाकी जो २५००करोड़ रूपया बिहार को नहीं मिलेगा, जितना यह सब ट्रांसमीशन का काम और बाकी जो काम चल रहा है, वह सारा काम बिहार में ठप्प पड़ जायेगा । इसलिए मैं विपक्ष और सत्ता पक्ष, सारे लोगों से आग्रह करूँगा कि केन्द्र की सरकार से बातचीत कर चार हजार करोड़ रूपया जो सम विकास योजना के तौर पर उसको बिहार को दिलाने की व्यवस्था करे ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिए जायेंगे ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को ले लिया जाय ।

अध्यक्ष : समय हो चुका है । २० मिनट समय आगे हो चुका है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, तीन बार यह प्रश्न स्थगित हुआ । मेरा और माननीय सदस्य श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव का प्रश्न ले लिया जाय ।

अध्यक्ष : अब अमरेन्द्र बाबू, इसके लिए समय कहाँ है हमलोगों के पास जो इसको लें ? अब तारांकित प्रश्न लेते हैं ।

(व्यवधान)

केवल मैं जबाब दिलवा देता हूँ ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : जी अच्छा ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- "ख"-४४ एवं "ग"- ४८

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, केवल जबाब माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह जी का और माननीय सदस्य श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव जी का जो जबाब है, उनको भेजवा दीजिएगा। उनको जबाब दे दीजिए ।

अब तारांकित प्रश्न लिए जायेंगे ।